

सितंबर 2020

## PRS की प्रमुख हाइलाइट्स

- **कोविड-19**
  - महामारी रोग (संशोधन) अधियक, 2020
  - कराधान और अन्य कानून (वभिन्न प्रावधानों में राहत) अधियक, 2020
  - दवाला और दवालापन संहति (दूसरा संशोधन) अधियक, 2020
  - राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष
- **समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास**
  - वर्ष 2020-21 की पहली तमिही में चालू खाता घाटा GDP के 3.9% पर
- **वित्त**
  - अर्हति वित्तीय संवदा द्वपिक्षीय नेटगि अधियक, 2020
  - बैंकगि वनियमन (संशोधन) अधियक, 2020
  - फैंकटरगि वनियमन (संशोधन) अधियक, 2020
  - स्टार्टअप इकोसिस्टम के वित्तपोषण पर रपिर्ट
- **शरम**
  - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थय तथा कार्यस्थति संहति अधियक, 2020
- **कृषि**
  - कसिन उपज व्यापार और वाणजिय अधियक, 2020
  - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधियक, 2020
  - खरीफ मौसम वर्ष 2020-21
  - रबी फसलों के लयि न्यूनतम समर्थन मूल्य
- **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण**
  - सहायक प्रजनन तकनीक (वनियमन) अधियक, 2020
  - राष्ट्रीय भारतीय चकितिसा प्रणाली आयोग अधियक, 2019
  - आयुर्वेद शकिषण और अनुसंधान संस्थान अधियक, 2020
  - राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधियक, 2020
- **गृह मामले**
  - वदिशी अंशदान (वनियमन) संशोधन अधियक, 2020
  - राष्ट्रीय फोरेंसिकि वजिज्ञान विश्वविद्यालय अधियक, 2020
  - राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधियक, 2020
  - जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा अधियक, 2020
- **कॉरपोरेट मामले**
  - कंपनी (संशोधन) अधियक, 2020
- **शकिषा**
  - भारतीय सूचना प्रौद्योगिकि संस्थान कानून (संशोधन) अधियक, 2020
  - ओपन और दूरस्थ शकिषा, ऑनलाइन कार्यक्रमों के लयि नयिम
- **नागरिक उड्डयन**
  - एयरक्राफ्ट (संशोधन) अधियक, 2020
- **वधि और न्याय**
  - आभासी न्यायालयों पर स्थायी समति की रपिर्ट
- **सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण**
  - ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020
- **वाणजिय और उद्योग**
  - रक्षा क्षेत्र में स्वचालति मार्ग से अधिकतम FDI
  - सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमकितता) आदेश, 2017
- **रक्षा**



- रक्षा अधगिरहण प्रक्रिया, 2020
- **कारमकि**
  - मशिन कर्मयोगी
- **इलेक्ट्रॉनिकिस एवं सूचना प्रौद्योगिकी**
  - 118 मोबाइल एप पर प्रतबिंध
- **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा**
  - ग्रीन टर्म अहेड मार्केट
- **जल संसाधन**
  - भूजल नकिसी को वनियमति और नयित्तरति करने के लयि दशिश-नरिदेश
- **सड़क परविहन**
  - केंद्रीय मोटर वाहन नयिमों में संशोधन
  - फास्टैग

## कोवडि-19

### • महामारी रोग (संशोधन) वधियक, 2020

महामारी रोग (संशोधन) वधियक, 2020 [Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020] संसद में पारति कयि गय। यह [महामारी रोग अधनियम, 1897](#) (Epidemic Diseases Act, 1897) में संशोधन करता है।

#### और पढ़ें

### • करधान और अन्य कानून (वभिनिन प्रावधानों में राहत) वधियक, 2020

करधान और अन्य कानून (वभिनिन प्रावधानों में राहत) वधियक, 2020 (Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020) को संसद में पारति कर दयि गय। यह वधियक मार्च 2020 में जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। वधियक आयकर अधनियम, 1961 (Income Tax Act, 1961) जैसे कुछ कर कानूनों के अनुपालन में राहत प्रदान करता है। यह राहत COVID-19 के प्रसार के कारण प्रदान की गई है।

- वधियक IT अधनियम के अंतर्गत रटिर्न फाइल करने और कटौतियों का दावा करने से संबंधति समय-सीमा को बढ़ाता है। यह केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है वह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधनियम, 2017 के अंतर्गत GST संबंधी अनुपालन और कार्रवाइयों की समयसीमा भी बढ़ा सकता है।

### • दवाला और दवालियापन संहति (दूसरा संशोधन) वधियक, 2020

दवाला और दवालियापन संहति (दूसरा संशोधन) वधियक, 2020 [Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020] संसद में पारति कर दयि गय है। यह 5 जून, 2020 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।

- अध्यादेश दवाला और दवालियापन संहति, 2016 में संशोधन करता है। संहति कंपनियों और व्यक्तियों के बीच दवालियापन के समाधान के लयि एक समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान करती है।
  - दवालियापन वह स्थिति है जब व्यक्ति या कंपनियों अपना बकाया ऋण नहीं चुका पाती हैं।
- वधियक में 25 मार्च, 2020 के बाद अगले 6 महीने तक कसि भी कंपनी के खलिफ इनसॉल्वेंसी की प्रक्रिया न शुरू करने की बात कही गई है। अतः यह केंद्र सरकार को इस अवधि को छह महीने तक बढ़ाने की अनुमति देता है।

### • राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

आपदा प्रबंधन अधनियम, 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लयि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की स्थापना को अनवार्य कयि गय है। गृह मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को COVID-19 की रोकथाम के लयि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund- SDRF) में मौजूद अधिकतम 50% राशिको खर्च करने की अनुमति दी है। यह सीमा पहले अधिकतम 35% नरिधारति थी।

यह अनुमति निम्नलिखति वय पर लागू होती है:

- (i) क्वारंटाइन, नमूना संग्रह और स्क्रीनिंग की सुवधि।
- (ii) COVID-19 के लयिआवश्यक उपकरणों/प्रयोगशालाओं की खरीद।

# समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

## • वर्ष 2020-21 की पहली त्रिमाही में चालू खाता घाटा GDP के 3.9% पर

वर्ष 2019-20 की पहली त्रिमाही (अप्रैल-जून) की तुलना में 2020-21 की इसी अवधि में भारत का चालू खाता घाटा 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 2.1%) से बढ़कर 19.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (GDP का 3.9%) हो गया। यह मुख्य रूप से वर्ष-दर-वर्ष निर्यात के मुकाबले आयात में अत्यधिक गिरावट के कारण हुआ है।

- पूंजी खाते में ऐसा लेन-देन शामिल होता है जो कि भारत में संस्थाओं की परसिंपत्त/दियता स्थिति में परिवर्तन करता है।
- पूंजी खाते में शुद्ध प्रवाह 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2019-20 की पहली त्रिमाही) से गरिकर 0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसका मुख्य कारण यह था कि वर्ष 2019-20 की पहली त्रिमाही में 18.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी निवेश का शुद्ध प्रवाह वर्ष 2020-21 की पहली त्रिमाही में गरिकर 0.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

## वित्त

### • अर्हति वित्तीय संवदि द्वपिकषीय नेटगि वधियक, 2020

अर्हति वित्तीय संवदि द्वपिकषीय नेटगि वधियक, 2020 (Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020) को संसद में पारति कर दिया गया। यह वधियक अर्हति वित्तीय संवदि की द्वपिकषीय नेटगि और क्लोज़-आउट नेटगि प्रबंधों के लिये कानूनी संरचना प्रदान करता है। वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **द्वपिकषीय नेटगि:** दो पक्षों के बीच सौदे से उत्पन्न दावों की भरपाई को नेटगि कहा जाता है जिसमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय या प्राप्त राशि का निर्धारण किया जाता है।
- **अर्हति वित्तीय संवदि (QFC):** QFC ऐसी द्वपिकषीय संवदि है जिसे संबंधित प्राधिकरण ने QFC के तौर पर अधिसूचित किया है। संबंधित प्राधिकरण भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतभूत और वनियमि बोरड (SEBI), भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) हो सकता है।
- **प्रयोज्यता:** वधियक के प्रावधान दो अर्हति बाज़ार भागीदारों के बीच QFC पर लागू होंगे जिनमें से कम-से-कम एक पक्ष नरिदषिट प्राधिकरण (RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA या IFSCA) द्वारा वनियमित होता है।
- **नेटगि का लागू होना:** वधियक में प्रावधान है कि QFC की नेटगि उस स्थिति में लागू की जाएगी जब संवदि में नेटगि का एग्रीमेंट हो।
  - नेटगि एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो या उससे अधिक QFC से संबंधित राशि की नेटगि का प्रावधान होता है।
  - नेटगि एग्रीमेंट में संपारश्वकि व्यवस्था भी शामिल हो सकती है।
    - संपारश्वकि व्यवस्था एक कसिम की सुरक्षा होती है जो कि नेटगि एग्रीमेंट में एक या उससे अधिक QFC को दी जाती है। इसमें संपत्तियों के लिये वचनबद्धता या संपारश्वकि या तीसरे पक्ष के गारंटर को टाइटल ट्रांसफर करने से संबंधित समझौता शामिल हो सकता है।
- **क्लोज़-आउट नेटगि की व्यवस्था:** क्लोज़-आउट नेटगि का अर्थ है संबंधित QFC के सभी दायित्वों का समाप्त होना। यह QFC से उत्पन्न होने वाले वर्तमान और भविष्य के दायित्वों का परसिमापन करता है, जिस पर नेटगि समझौता लागू होता है। इस प्रक्रिया को डिफॉल्ट या समाप्ति की घटना (जैसा कि नेटगि एग्रीमेंट में नरिदषिट हो, जोकि एक या दोनों पक्षों को एग्रीमेंट के अंतर्गत लेन-देन को समाप्त करने का अधिकार देती हो) की स्थिति में शुरू किया जा सकता है। क्लोज़-आउट नेटगि के अंतर्गत शुद्ध राशि नमिनलखिति के ज़रिये नरिधारति की जाएगी:
  - (i) पक्षों द्वारा किये गए नेटगि एग्रीमेंट के अनुसार।
  - (ii) पक्षों के बीच एग्रीमेंट के ज़रिये।
  - (iii) मध्यस्थता के ज़रिये।

### • बैंकगि वनियमन (संशोधन) वधियक, 2020

बैंकगि वनियमन (संशोधन) वधियक, 2020 [Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020] संसद में पारति हो गया है। यह बैंकगि वनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) में संशोधन करता है। यह अधिनियम बैंकों की लाइसेंसिंग, प्रबंधन और परचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नयित्तरति करता है।

## और पढ़ें

### • फ़ैक्टरगि वनियमन (संशोधन) वधियक, 2020

फ़ैक्टरगि वनियमन (संशोधन) वधियक, 2020 को लोकसभा में पेश किया गया। यह वधियक फ़ैक्टरगि वनियमन अधिनियम, 2011 में संशोधन करता है और फ़ैक्टरगि बज़िनेस करने वाली संस्थाओं के दायरे को बढ़ाता है।

- फ़ैक्टरगि वनियमन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत फ़ैक्टरगि बज़िनेस एक ऐसा बज़िनेस होता है जिसमें एक संस्थान (जिसे फ़ैक्टर कहा जाता है) दूसरे संस्थान (जिसे एसाइनर कहा जाता है) की प्राप्तियों को एक राशि के बदले प्राप्त करता है।

- प्राप्य वह कुल राशि होती है जो किसी वस्तु, सेवा या सुविधा के उपयोग के कारण ग्राहकों (जन्हें ऋणी कहा जाता है) पर बकाया होती है या जिसका भुगतान उनके द्वारा किया जाना होता है।
- फ़ैक्टर बैंक एक पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी हो सकती है। वधियक के मुख्य प्रावधानों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - **फ़ैक्टर का पंजीकरण:** अधिनियम के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के साथ पंजीकरण किये बिना कोई भी कंपनी फ़ैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न नहीं हो सकती है। अगर किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company- NBFC) को फ़ैक्टरिंग व्यवसाय करना हो तो:
    - फ़ैक्टरिंग व्यवसाय में उसकी वित्तीय संपत्ति, और
    - फ़ैक्टरिंग व्यवसाय से उसकी आय दोनों को उसके सकल संपत्तिया शुद्ध आय के 50% से अधिक या RBI द्वारा अधिसूचिता सीमा से अधिक होना चाहिये। वधियक में NBFC के लिये फ़ैक्टरिंग व्यवसाय की इस सीमा को हटा दिया गया है।
  - **लेन-देन का पंजीकरण:** अधिनियम के अंतर्गत फ़ैक्टर को अपने पक्ष में प्राप्तियों के (Assignment) के प्रत्येक वविरण का पंजीकरण करना होगा। इन वविरणों को 30 दिनों की अवधि के दौरान केंद्रीय रजिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाना चाहिये जो कवित्तीय आस्तियों का प्रतभूतकरण और पुनर्गठन तथा प्रतभूत हति का प्रवर्तन अधिनियम-सरफेसी (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest- SARFAESI), 2002 के अंतर्गत गठित हो। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी का अनुपालन न करने के कारण प्रत्येक अधिकारी को तब तक प्रतदिनि 5 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है जब तक कडिफ़ॉल्ट जारी रहता है।
    - वधियक 30 दिनों की इस अवधि को हटाता है और यह कहता है कि समय, अवधि, पंजीकरण के तरीके और देर से पंजीकरण के भुगतान शुल्क के वनियमन द्वारा नरिदषित किया जा सकता है।
- इसके अतरिकृत वधियक में कहा गया है कि जहाँ व्यापार प्राप्तियों को **व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली** (Trade Receivable Discounting System-TReDS) के माध्यम से वतितपोषित किया जाता है वही फ़ैक्टर की तरफ से लेन-देन के वविरणों से संबंधित TReDS द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री में उपक्रमों को फाइल किया जाना चाहिये। उल्लेखनीय है कि TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों की ट्रेडिंग प्राप्तियों के वतितपोषण को सुगम बनाता है।

#### • स्टार्टअप इकोसिस्टम के वतितपोषण पर रपिर्त

वतित संबंधी स्थायी समति (अध्यक्ष: जयंत सनिहा) ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के वतितपोषण पर अपनी रपिर्त प्रस्तुत की। समति ने सुझाव दिया कि स्टार्टअप में नविश अवसरों को व्यापक बनाने और घरेलू नविशकों की भागीदारी में सुधार के लिये कराधान और अन्य वनियमन में बदलाव किया जाए।

[और पढ़ें](#)

## शरम

#### • व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थति संहिता वधियक, 2020

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थति संहिता वधियक, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया है। यह संहिता स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्यस्थतियों को वनियमित करने वाले 13 मौजूदा अधिनियमों को एकीकृत करती है।

[और पढ़ें](#)

## कृषि

#### • कसिन उपज व्यापार और वाणजिय वधियक, 2020

कसिन उपज व्यापार और वाणजिय (संवर्द्धन और सुविधा) वधियक, 2020 [Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020] को संसद में पारित किया गया है। वधियक जून 2020 में जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।

[और पढ़ें](#)

#### • आवश्यक वस्तु (संशोधन) वधियक, 2020

आवश्यक वस्तु (संशोधन) वधियक, 2020 [Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020] को संसद में पारित किया गया है। यह वधियक 5 जून, 2020 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। यह वधियक [आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955](#) [Essential Commodities Act, 1955] में संशोधन करता है।

[और पढ़ें](#)

#### • खरीफ मौसम वर्ष 2020-21

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture and Farmers) ने खरीफ मौसम वर्ष 2020-21 के लिये खाद्यान्न और वाणज्यिक फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी किया है। इस संबंध कुछ तथ्य इस प्रकार हैं:

- खरीफ वर्ष 2019-20 की तुलना में खरीफ वर्ष 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन में 0.8% की गिरावट हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से दालों के उत्पादन में 20.6% की गिरावट के कारण हुई।
- मूँगफली के उत्पादन में 14% की वृद्धि और सोयाबीन के उत्पादन में 21.1% की वृद्धि अनुमानित है।
- वर्ष 2020-21 में कपास के उत्पादन में 4.6% की वृद्धि का अनुमान है और गन्ने का उत्पादन 12.4% बढ़कर लगभग 400 मिलियन टन होने का अनुमान है।

#### • रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 में रबी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Prices- MSP) को मंजूरी दी है।

[और पढ़ें](#)

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

#### • सहायक प्रजनन तकनीक (वनिियमन) विधियक, 2020

सहायक प्रजनन तकनीक (वनिियमन) विधियक, 2020 [Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020] को लोकसभा में पेश किया गया। यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के वनिियमन का प्रावधान करने का प्रयास करता है।

[और पढ़ें](#)

#### • राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधियक, 2019

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधियक, 2019 (National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019) संसद में पारित किया गया है। यह विधियक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 को नरिस्त करता है।

[और पढ़ें...](#)

[राष्ट्रीय आयोग विधियक- 2020 \(भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी\)](#)

[राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधियक, 2019](#)

#### • आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधियक, 2020

आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान विधियक, 2020 (Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020) को संसद में पारित किया गया। विधियक की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **वलय:** विधियक तीन आयुर्वेद संस्थानों का वलय कर एक संस्थान आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान बनाने का प्रयास करता है। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के परिसर में स्थित होगा। विधियक इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित करता है।

**संस्थान के कार्य:** संस्थान के कार्यों में नमिनलखित शामिल हैं:

- आयुर्वेद की स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा (फार्मेसी सहित) का प्रावधान।
- आयुर्वेद में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये पाठ्यक्रम और करिकुलम नरिदषिट करना।
- आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना।
- आयुर्वेद और फार्मेसी में परीक्षाएँ संचालित करना, डगिरी, डपिलोमा और दूसरे डिस्टिक्शंस और टाइटलि देना।

#### • राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधियक, 2020

राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधियक, (National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill) 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया। विधियक संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय की शिक्षा तथा अभ्यास को वनिियमति एवं मानकीकृत करने का प्रयास करता है। विधियक की प्रमुख विशेषताओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- **परिभाषा:** विधियक के अनुसार 'संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय' उस सहयोगी, तकनीशियन या प्रौद्योगिकीविद् को कहा जाएगा जो किकिसी

बीमारी, रोग, चोट या क्षतिके नदिान और उपचार में सहयोग देने के लिये प्रशिक्षित हो। इसके अतिरिक्त संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय को वधियक के अंतर्गत डप्लोमा या डिग्री प्राप्त होनी चाहिये। डप्लोमा या डिग्री की अवधिकम-से-कम 2,000 घंटे (दो से चार वर्ष की अवधि के दौरान) होनी चाहिये।

- **संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय:** वधियक अनुसूची में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय की कुछ मान्यता प्राप्त श्रेणियों को नरिदषिट करता है। इनमें लाइफ साइंस प्रोफेशनल, टर्मा एंड बर्न केयर प्रोफेशनल, सर्जिकल और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोफेशनल, फजियोथेरेपिस्ट तथा न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग:** वधियक राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग की स्थापना करता है जो की नीतियों और मानक बनाने, सभी पंजीकृत व्यवसायों के लिये ऑनलाइन केंद्रीय रजिस्टर बनाने और उसका रखरखाव करने, शक्तिषण तथा प्रशक्तिषण के बुनियादी मानदंड बनाने तथा समान प्रवेश और नकिस परीक्षाओं का प्रावधान करने लिये उत्तरदायी होगा।
- **राज्य परषिदें:** राज्य सरकार को वधियक पारति होने के छह महीने के भीतर संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा परषिदों का गठन करना होगा। यह व्यावसायिक आचरण/आचार को लागू करने, राज्य स्तरीय रजिस्ट्रों का रख-रखाव करने, संस्थानों का नरीक्षण और समान प्रवेश एवं नकिस परीक्षाएँ सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- **अपराध और सज़ा:** राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित योग्य संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ती को अभ्यास करने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ती को 50,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

## गृह मामले

### • वदिशी अंशदान (वनिधियम) संशोधन वधियक, 2020

वदिशी अंशदान (वनिधियम) संशोधन वधियक, 2020 [Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020] को संसद में पारति किया गया है। यह वधियक वदिशी अंशदान (वनिधियम) अधनिधियम, 2010 [Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010] में संशोधन करता है।

### और पढ़ें

### • राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय वधियक, 2020

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय वधियक, 2020 (National Forensic Sciences University Bill, 2020) को संसद में पारति कर दिया गया। वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **विश्वविद्यालय की स्थापना:** वधियक गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधी नगर (गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधनिधियम, 2008 के अंतर्गत स्थापति) तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान (Lok Nayak Jayaprakash Narayan National Institute of Criminology and Forensic Sciences), नई दलिली को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में स्थापति करता है। वधियक इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषति करता है। वधियक 2008 के अधनिधियम को रद्द करता है। विश्वविद्यालय परसिरों में दोनों विश्वविद्यालयों के परसिर और दूसरे अन्य परसिरों को अधसूचित किया जा सकता है।
- **कार्य:** विश्वविद्यालय के कार्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - (i) फोरेंसिक विज्ञान, एप्लाइड बहिवियरल विज्ञान, कानून और अपराध विज्ञान में प्रशक्तिषण तथा अनुसंधान का प्रावधान।
  - (ii) कॉलेजों, स्कूलों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उनका संचालन।
  - (iii) पाठ्यक्रम नरिधारति करना, परीक्षाएँ कराना और डिग्री एवं अन्य उपाधियाँ प्रदान करना।

### • राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वधियक, 2020

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय वधियक, 2020 (Rashtriya Raksha University Bill, 2020) को संसद में पारति कर दिया गया है। वधियक की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **विश्वविद्यालय की स्थापना:** वधियक रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात [रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधनिधियम, 2009 (Raksha Shakti University Act, 2009) के अंतर्गत स्थापति] को गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापति करता है। वधियक इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषति करता है। यह वधियक 2009 के अधनिधियम को रद्द करता है।
- **कार्य:** विश्वविद्यालय के कार्यों में शामिल हैं:
  - (i) पुलिस विज्ञान में नरिदेश और अनुसंधान प्रदान करना जिसमें कोस्टल पुलिसिगि और साइबर सुरक्षा शामिल है।
  - (ii) कॉलेजों की स्थापना और उनका संचालन।
  - (iii) पाठ्यक्रम नरिधारति करना, परीक्षाएँ संचालति करना और डिग्री एवं अन्य उपाधियाँ प्रदान करना।

### • जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा वधियक, 2020

जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा वधियक, (Jammu and Kashmir Official Languages Bill) 2020 को संसद में पारति किया गया। वधियक कुछ भाषाओं को केंद्रशासति प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषाएँ घोषति करने का प्रयास करता है।

- **आधिकारिक भाषा:** वधियक कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हदिी और अंगरेज़ी को केंद्रशासति प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में आधिकारिक उद्देश्य से उपयोग

होने वाली आधिकारिक भाषाएँ घोषित करता है। यह प्रावधान उस तारीख से लागू होगा जिस तारीख को केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन अधिसूचित होगा। वधियक में प्रावधान है कि केंद्रशासित प्रदेश की वधानसभा इन आधिकारिक भाषाओं काम करेगी।

- **अंग्रेज़ी का उपयोग:** वधियक स्पष्ट करता है कि अधिनियम के लागू होने से पहले जनि प्रशासनिक और वधियी उद्देश्यों के लिये अंग्रेज़ी का उपयोग होता था उनके लिये अब भी अंग्रेज़ी का उपयोग होता रहेगा।

[और पढ़ें](#)

## कॉर्पोरेट मामले

### • कंपनी (संशोधन) वधियक, 2020

कंपनी (संशोधन) वधियक, [Companies (Amendment) Bill] 2020 संसद में पारित कर दिया गया। यह वधियक कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act, 2013) में संशोधन करता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अपराधों में परिवर्तन:** यह वधियक तीन प्रमुख परिवर्तन करता है। पहला, वह 23 प्रशम्य (Compoundable) अपराधों को संस्थानिक मध्यस्थता के अंतर्गत लाता है जिसमें जुर्माना/कारावास की जगह जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरा, 11 अपराधों के लिये कारावास के स्थान पर सरिफ जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरा, सात अपराधों को हटा दिया गया है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):** अधिनियम के अंतर्गत एक नरिदषिट राशिके मूल्य, टर्नओवर या लाभ कमाने वाली कंपनियों से CSR समतियों का गठन करने और पछिले तीन वत्तीय वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% अपनी CSR नीतिपर खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। वधियक उन कंपनियों को CSR समतियों के गठन से छूट देता है जिनकी CSR देनदारी प्रतविरष अधिकतम 50 लाख रुपए है। इसके अतरिकित किसी वत्तीय वर्ष में अपने CSR बाध्यता से अधिक धनराशि खर्च करने पर अगले वत्तीय वर्ष की CSR बाध्यता में अतरिकित राशि जुड़ सकती है।
- **वदिशी कषेत्राधिकारों में प्रतयकष सूची:** वधियक केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को वदिशी कषेत्राधिकार में प्रतभूतियों की श्रेणियों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दे सकती है।

## शिक्षा

### • भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) वधियक, 2020

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) वधियक, 2020 [Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020] को संसद में पारित किया गया है। यह वधियक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 (Indian Institutes of Information Technology Act, 2014) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-नजि भागीदारी) अधिनियम, 2017 [Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017] में संशोधन करता है।

[और पढ़ें](#)

### • ओपन और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिये नयिम

वशिवदियालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) ने वशिवदियालय अनुदान आयोग (ओपन और दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन कार्यक्रम) वनियम, 2020 को अधिसूचित किया। वनियम ओपन और दूरस्थ शिक्षा मोड और ऑनलाइन मोड के माध्यम से डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने के लिये न्यूनतम मानकों को नरिधारित करते हैं। संस्थान केवल उन्हीं ओपन और दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन कार्यक्रमों को पेश करते हैं जनिहें कक्षा शकिषण के परंपरागत मोड के अंतर्गत पेश किया जाता है। वनियम नमिनलखिति प्रावधान करते हैं:

- **ओपन और दूरस्थ शिक्षा (ODL) कार्यक्रम:** उच्च शकिषण संस्थानों को ODL मोड में कार्यक्रम पेश करने के लिये नमिनलखिति मानदंडों को पूरा करना होगा:
  1. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (National Assessment and Accreditation Council -NAAC) द्वारा 3.01 (4 में से) का न्यूनतम प्रत्यायन स्कोर।
  2. आवेदन के समय दो पूर्ववर्ती चक्रों में कम-से-कम एक में राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (National Institute Ranking Framework-NIRF) के अंतर्गत शीर्ष 100 वशिवदियालयों की रैंकिंग में स्थान।
- **ऑनलाइन पाठ्यक्रम:** संस्थानों को ऑनलाइन कार्यक्रमों की पात्रता के लिये नमिनलखिति मानदंडों को पूरा करना होगा:
  1. NAAC प्रत्यायन स्कोर का 3.26 या उससे अधिक (4 में से) होना।
  2. तीन पूर्ववर्ती चक्रों में से कम-से-कम एक में NIRF के अंतर्गत शीर्ष 100 वशिवदियालयों की रैंकिंग में स्थान।

ऐसे पात्र संस्थान UGC की मंजूरी के साथ ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।

- **कार्यक्रम:** पात्र संस्थान नरिदषिट प्रतबिधित कार्यक्रमों के अतरिकित अन्य कषेत्रों में डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान कर सकते हैं। प्रतबिधित कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग, चकितिसा, वास्तुकला, कानून और कृषि आदि कषेत्र शामिल हैं।
- **गुणवत्ता मानक:** ODL या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले सभी संस्थानों को आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन के लिये एक केंद्र की

स्थापना करनी चाहिये। इस केंद्र का प्रमुख एक नदिशक (एसोसिएट प्रोफेसर या उससे उच्च पद का) होगा। यह केंद्र ODL और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। ODL और ऑनलाइन कार्यक्रमों के कुल क्रेडिट परंपरागत मोड के उन्हीं कार्यक्रमों के समान होंगे।

## नागरिक उड्डयन

### • एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधियक, 2020

एयरक्राफ्ट (संशोधन) विधियक, 2020 [Aircraft (Amendment) Bill, 2020] को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। विधियक एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 (Aircraft Act, 1934) में संशोधन का प्रयास करता है। अधिनियम सविलि एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उन पर कब्जा, इस्तेमाल, परिचालन, बिक्री, आयात और निर्यात तथा एयरोड्रोमस की लाइसेंसिंग को वनियमिति करता है। विधियक के मुख्य प्रावधानों में नमिनलिखित शामिल हैं:

- **अथॉरिटीज़:** विधियक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा नकियाँ को अधिनियम के तहत वैधानिक नकियाँ बनाता है। ये अथॉरिटीज़ हैं:
  1. नागर वमिानन महानदिशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA)
  2. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security- BCAS)
  3. वमिान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (Aircraft Accidents Investigation Bureau- AAIB)।

इनमें से प्रत्येक नकियाँ का एक डायरेक्टर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।

- DGCA कानून या कानून के अंतर्गत अधिसूचित नियमों में नरिदषिट सुरक्षा नरिीक्षण और नयामक कार्यों को पूरा करेगा (इनमें नागरिक वायु वनियम, वायु सुरक्षा और वायु सुरक्षा मानक शामिल हो सकते हैं)। BCAS अधिनियम के अंतर्गत नरिदषिट नागरिक उड्डयन सुरक्षा से संबंधित वनियामक नरिीक्षण कार्यों को पूरा करेगा (ये हवाई अड्डे के संचालक, एयरलाइंस संचालक और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिये हो सकते हैं)। AAIB वमिान दुर्घटनाओं और हादसों से संबंधित जाँच करेगा।
- **अपराध और सज़ा:** अधिनियम के अंतर्गत वभिनिन अपराधों के लिये अधिकतम दो वर्ष की सज़ा या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है। इन अपराधों में नमिनलिखित शामिल हैं:
  - (i) एयरक्राफ्ट में हथियार, वसिफोटक या दूसरी खतरनाक वस्तुएँ ले जाना।
  - (ii) अधिनियम के अंतर्गत कर्सी नरिदषिट नियम का उल्लंघन करना।
  - (iii) एयरोड्रोम रेफरेंस प्वाइंट के इर्रद-गरिद के रेडियस में बलिडिंग बनाना या दूसरे प्रकार के कंस्ट्रक्शन करना। विधियक इन सभी अपराधों पर जुर्माने को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक करता है।

## वधि और न्याय

### • आभासी न्यायालयों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट

कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: भूपेन्द्र यादव) ने आभासी न्यायालयों की कार्यपद्धति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि देश के पारिस्थितिकी तंत्र में आभासी अदालतों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। मुख्य सुझावों में नमिनलिखित शामिल हैं:

- **डिजिटल डेविड:** समिति ने कहा कि बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं और वादियों को बुनियादी ढाँचा और हाई स्पीड जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं जो आभासी सुनवाई के लिये बहुत आवश्यक हैं। इस समस्या को हल करने के लिये नजिी एजेंसियों को शामिल करने की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिये ताकि उन लोगों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों की सुविधा सुनिश्चित हो सके जो कतिक्नीक के जानकर (Tech-savvy) नहीं हैं। इससे वे लोग न्यायालयों से जुड़ पाएंगे।
- **कनेक्टविटी डेविड:** कनेक्टविटी डेविड पर समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मशिन का समय पर कार्यान्वयन करने के लिये प्रयासों में तेज़ लानी चाहिये।
  - सकलि डेविड: इस पर समिति ने सुझाव दिया है कि देश के सभी न्यायालय परिसरों में प्रशक्किण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये ताकि अधिवक्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिये ज़रूरी दक्षता हासिल हो। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि भारतीय बार परिषद (Bar Council of India) को कॉलेजों में कानून के पाठ्यक्रम के साथ कंप्यूटर पाठ्यक्रम को भी एक वषिय के तौर पर शुरू करना चाहिये।
- **अधीनस्थ न्यायालय:** समिति ने कहा कि नचिली अदालतों में बुनियादी ढाँचा मौजूद नहीं है और उन्हें आभासी न्यायालयों को अपनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चूँकि आभासी न्यायालयों में शुरुआत में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिये समिति ने सुझाव दिया कि सार्वजनिक-नजिी भागीदारी मॉडल जैसे वतितपोषण के नए तरीकों की तलाश की जानी चाहिये।
- **आभासी न्यायालयों को जारी रखना:** समिति ने सुझाव दिया कि कुछ नरिदषिट प्रकार की अपीलें और अंतिम सुनवाईयों (जहाँ शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं) में सभी पक्षों की सहमति से प्रायोगिक आधार पर आभासी सुनवाईयों की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाए।
- **आगे का रास्ता:** समिति ने सुझाव दिया कि बार संघों और बार परिषदों (Bar Associations and Bar Councils) के सदस्यों के परामर्श से पायलट आधार पर पूरण रूप से आभासी न्यायालय प्रणाली को लागू किया जाए। समिति ने यह सुझाव भी दिया कि जनि मामलों में व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, उन सभी को आभासी न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये। जनि मामलों में कानून और तथ्यों की व्याख्या करनी हो तथा बड़ी संख्या में गवाहों की जाँच करनी हो, उनमें मैन्युअल प्रक्रियाओं (जैसे कि शिकायत दर्ज करना और सम्मन जारी करना) के डिजिटलीकरण के



लघि हाइब्रडि मॉडल को अपनाया जा सकता है और सुनवाई फ़ज़िकल अदालतों में की जा सकती है ।

[और पढ़ें](#)

## सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण

### • ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020

ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकारों का संरक्षण) नयिम, 2020 अधिसूचि कयिा गया । इन नयिमों को ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकारों का संरक्षण) अधिनयिम, 2019 के अंतरगत अधिसूचि कयिा गया है । अधिनयिम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और संरक्षण का प्रावधान करता है । नयिमों में मुख्य रूप से नमिनलखि वशिषताएँ शामिल हैं:

- **पहचान प्रमाणपत्र जारी करना:** अधिनयिम के अंतरगत ट्रांसजेंडर व्यक्ती को पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लघि ज़िला मजसि्ट्रेट को आवेदन करना होगा । आवेदन के लघि नयिमों में अपेक्षा की गई है कि आवेदनपत्र के साथ लैंगकि पहचान वाला एक शपथ पत्र जमा कराया जाएगा ।
- नाबालगि की स्थति में माता-पति या अभिावक यह आवेदन कर सकते हैं । जसि बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होगी उसके लघि कशिोर न्याय अधिनयिम, 2015 के अंतरगत गठि बाल कल्याण समति आवेदन करेगी ।
- प्रमाणपत्र को 30 दनिों के भीतर जारी कयिा जाना चाहयि । ज़िला मजसि्ट्रेट ट्रांसजेंडर को पहचानपत्र भी जारी करेगा । ज़िला मजसि्ट्रेट कसिी आवेदक को उस स्थति में प्रमाणपत्र जारी कर सकता है यदविह उसके कषेत्राधिकार में पछिले 1 वर्ष से लगातार रह रहा हो ।
- **संशोधति प्रमाणपत्र जारी करना:** यदविह व्यक्ती ने सेक्स रअिसाइनमेंट सर्जरी कराई है तो सर्जरी करने वाले अस्पताल के चकित्सिा अधीकषक या मुख्य चकित्सिा अधिकारी द्वाारा जारी एक प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा । उस व्यक्ती का पुरुष या महिला जेंडर वाला संशोधति प्रमाणपत्र 15 दनिों के भीतर जारी कयिा जाएगा ।
- **अपील:** यदविह पहचान प्रमाणपत्र का आवेदन रदद कर दयिा जाता है, तो आवेदक 90 दनिों के भीतर इस फैसले के वरिद्ध (अधिसूचि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष) अपील कर सकता है ।
- **कल्याणकारी उपाय:** केंद्र और राज्य सरकार चकित्सिा बीमा, ट्रांसजेंडर छात्रों के लघि छात्रवृत्त और सस्ते आवास आदि कल्याणकारी योजनाएँ तैयार कर सकती है । सभी शैक्षणिक संस्थानों में एक ऐसी समति होनी चाहयि जसिसे उत्पीडन या भेदभाव की स्थति में ट्रांसजेंडर व्यक्ती संपर्क कर सके । इसके अतरिकित सभी प्रतषिठानों में एक समान अवसर नीततिथा शकियत अधिकारी होना चाहयि ।

## वाणज्य और उद्योग

### • रक्षा कषेत्र में स्वचालति मारग से अधिकितम FDI

वाणज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने रक्षा कषेत्र में प्रत्यक्ष वदिशी नविश (Foreign Direct Investment-FDI) नीतति में परविरतनों को अधिसूचि कर दयिा है । यह नीतति कषेत्र की उन कंपनियों पर लागू होती है जो उद्योग (वकिस और वनियिमन) अधिनयिम, 1951 [Industries (Development & Regulation) Act, 1951] और [आयुध अधिनयिम, 1959](#) (Arms Act, 1959) के अंतरगत लाइसेंसि के अधीन हैं ।

[और पढ़ें](#)

### • सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडयिा को प्राथमकिता) आदेश, 2017

वाणज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) ने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडयिा को प्राथमकिता) आदेश, [Public Procurement (Preference to Make in India) Order], 2017 में संशोधन कयिा है । संशोधन सरकारी खरीद अनुबंधों में स्थानीय आपूर्तकिर्त्ताओं को प्राथमकिता देने का प्रावधान करता है । 2017 का आदेश स्थानीय सामग्री की मात्रा के आधार पर आपूर्तकिर्त्ताओं को वर्गीकृत करता है:

- वर्ग- I स्थानीय आपूर्तकिर्त्ता (50% या उससे अधिक) ।
- वर्ग- II स्थानीय आपूर्तकिर्त्ता (20%-50%) ।
- वर्ग- III गैर-स्थानीय आपूर्तकिर्त्ता (20% से कम) ।

भारत में मूल्य संवर्द्धन की मात्रा स्थानीय सामग्री होती है जसकि गणना कसिी वस्तु के कुल मूल्य से आयातति सामग्री की मात्रा को घटाकर (कुल मूल्य के प्रतशित के रूप में) की जाती है । संशोधन के मुख्य प्रावधानों में नमिनलखि शामिल हैं:

- **अनेक बोलीकृत्ताओं के अनुबंधों में भी प्राथमकिता का प्रावधान:** वर्ग- I के आपूर्तकिर्त्ताओं को दी जाने वाली प्राथमकिता उन नविदिाओं पर लागू होती है जसिमें कई बोली लगाने वालों को अनुबंध दयिा जाता है । इसमें प्राथमकिता इस प्रकार है:
  - जहाँ पर्याप्त स्थानीय क्षमता है वहाँ अन्य आपूर्तकिर्त्ताओं की भागीदारी को प्रतबिंधति करना ।
  - यह सुनश्चि करना कि कम-से-कम 50% अनुबंध वर्ग- I के आपूर्तकिर्त्ताओं द्वारा पूरा कयिा जाए, जो इस शर्त के अधीन है कि उन आपूर्तकिर्त्ताओं का मूल्य प्राथमकिता की सीमा के भीतर आता हो । प्राथमकिता का दायरा वह अधिकितम सीमा होती है जसिमें वर्ग- I के आपूर्तकिर्त्ताओं द्वारा उद्धत मूल्य अनुबंध के लघि मलिी सबसे कम बोली से अधिक हो सकता है ।
- **वदिशी भागीदारी के लघि संयुक्त उपक्रम:** जनि वस्तुओं की खरीद के लघि नोडल मंत्रालय ने यह अधिसूचि नहीं कयिा है कि उसके पास पर्याप्त स्थानीय क्षमता है, उन नविदिाओं को वदिशी कंपनियों भर सकती है । एक सीमा से अधिक वाले अधिसूचि अनुबंधों के लघि वदिशी कंपनियों कसिी

भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम के माध्यम से भागीदार बन सकती हैं।

- **स्थानीय सामग्री की सीमा:** संशोधन वर्ग- I और वर्ग- II के आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये स्थानीय सामग्री की सीमा को क्रमशः 50% और 20% पर बरकरार रखता है। जो स्पष्ट करता है किये न्यूनतम सीमाएँ हैं और यह कि नोडल मंत्रालय सरिफ स्थानीय सामग्री की अधिकतम सीमा नरिदषिट कर सकता है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय की सामग्री की न्यूनतम सीमा से छूट देने की शक्ति अब भी लागू होती है।
- **वदिशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर प्रतर्बिध:** आदेश में नोडल मंत्रालय को अनुमति दी गई है कि विह कुछ देशों की कंपनियों को खरीद अनुबंध में भाग लेने से प्रतर्बिधति कर सकता है यदि उसे पता चलता है कि उन्ही वस्तुओं के भारतीय आपूर्तिकर्त्ताओं को इन देशों की सरकारी खरीद में भाग लेने से रोका गया है। ऐसे देशों की कंपनियों को रोकने या न रोकने का नरिणय लेने का अधिकार नोडल मंत्रालय के वविकाधीन है। संशोधन सरिफ मंत्रालय द्वारा प्रकाशति वस्तुओं की एक सीमति सूची के अतरिकित बाकी सभी खरीद अनुबंधों में इन देशों की कंपनियों को भाग लेने से रोकता है।

## रक्षा

### • रक्षा अधगिरहण प्रकरिया, 2020

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधगिरहण प्रकरिया (Defence Acquisition Procedure- DAP), 2020 का मसौदा जारी किया है। DAP मसौदा रक्षा खरीद प्रकरिया, 2016 का स्थान लेता है। यह 1 अक्तूबर, 2020 से 30 सतिंबर, 2025 तक या संशोधति होने तक जारी रहेगा।

[और पढ़ें](#)

## कार्मकि

### • मशिन कर्मयोगी

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने सविलि सेवा सदस्यों के लिये राष्ट्रिय सविलि सेवा क्षमता वकिस कार्मकर्म (National Programme for Civil Services Capacity Building- NPCSCB) शुरु करने की मंजूरी प्रदान की है।

[और पढ़ें](#)

## इलेक्ट्रॉनकिंस एवं सूचना प्रौद्योगकिी

### • 118 मोबाइल एप पर प्रतर्बिध

इलेक्ट्रॉनकिंस और सूचना प्रौद्योगकिी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने 118 एप्स को इस आधार पर प्रतर्बिधति कर दिया कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनकि वयवस्था के लिये खतरा हैं। इन एप्स में पबजी मोबाइल लाइट, एलीपे और बाइडू शामिल हैं। मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों पर इन एप्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। जून 2020 में मंत्रालय ने इसी तरह के आधार पर TikTok, Shareit, UC Browser और Cam Scanner सहति 59 मोबाइल एप्स पर प्रतर्बिध लगाया था।

## नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

### • ग्रीन टर्म अहेड मार्केट

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry for New and Renewable Energy) ने 1 सतिंबर, 2020 को ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market- GTAM) की शुरुआतकी की। टर्म अहेड मार्केट, ऐसा मार्केट प्लेटफॉर्म है जसिमें उर्जा का अधिकतम 11 दनिों की अवर्धा के आधार कारोबार किया जा सकता है। GTAM से अक्षय ऊर्जा की अल्पकालकि खरीद में प्रतर्बिध मूल्य और पारदर्शति सुनशिचति होगी। मार्केट की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- GTAM अनुबंधों को सोलर नवीकरणीय वदियुत दायतित्वों (Renewable Power Obligations- RPO) और गैर-सोलर RPO में वर्गीकृत किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बजिली की न्यूनतम नरिदषिट मात्रा के उत्पादन या खरीद के लिये RPO अनविर्य है। अनुबंधों की परभिषा में ग्रीन इंटरा डे, डे अहेड कंटीजेंसी, दैनकि या साप्ताहकि अनुबंध शामिल हैं।
- GTAM अनुबंधों के माध्यम से खरीदी गई बजिली को खरीदार पर लागू RPO लक्ष्य के अंतरगत माना जाएगा।
- प्राइज टाइम प्रायोरटि/प्राथमकिता के आधार पर मूल्य तय किये जाएंगे। प्राइज टाइम प्रायोरटि के आधार पर बोलियों और प्रस्तावों को उनके नषिपादन के मूल्य के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। एक ही मूल्य की दो बोलियों या प्रस्तावों की स्थति में व्यापार प्लेटफॉर्म में पहले दर्ज की गई बोली या प्रस्ताव को पहला रैंक दिया जाएगा।

## जल संसाधन

### • भूजल नकिसी को वनियमति और नरित्तरति करने के लिये दशिा-नरिदेश

जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) ने देश में भूजल निकासी को वनियमिति और नयितरति करने के लिये दशा-नरिदेश जारी किये हैं। ये दशा-नरिदेश वर्ष 2018 के उन दशा-नरिदेशों को प्रतस्थापति करते हैं जनिहें वर्ष 2019 में नेशनल ग्रीन टरबियूनल ने रद कर दिया था। नेशनल ग्रीन टरबियूनल ने कहा था कि वर्ष 2018 के दशा-नरिदेश अपरहार्य हैं और अगर इन्हें लागू किया गया तो भूजल का स्तर तेज़ी से गरिगा तथा जलाशयों को नुकसान होगा। नए दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **नो ऑब्जेकशन सर्टफिकेट (NOC):** भूजल निकासी करने वाले सभी उद्योगों, बुनयिादी ढाँचा परयोजनाओं और खनन परयोजनाओं को केंद्रीय भूजल प्राधकिरण या संबंघति राज्य भूजल प्राधकिरण से NOC लेने की आवश्यकता होगी।
- **छूट:** उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों को भूजल निकासी के लिये NOC लेने से छूट दी जाएगी। इसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
  1. पेयजल और घरेलू उपयोग के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तगित घरेलू उपभोक्ता।
  2. सशस्त्र बलों के संस्थापन एवं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बल की स्थापना।
  3. कृषि संबंधी गतविधियाँ।
  4. प्रतदिनि 10 घन मीटर से कम पानी नकिलने वाले सूक्ष्म और लघु उपकरम।
- **कृषि उपयोग:** राज्य कसिानों को बजिली मुफ्त या सब्सडी पर देने की नीति पर वचिार कर सकते हैं। वे जल मूल्य नरिधारण नीति बिनाने तथा फसल चक्रीकरण, वविधीकरण तथा अन्य उपायों पर वचिार कर सकते हैं ताकि कसिान भूजल पर बहुत अधकि नरिभर न रहें।

**भूजल का ऐब्सट्रैकशन शुल्क:** दशा-नरिदेशों में वभिनि प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिये भूजल संकषेण (Abstraction) शुल्क की दरें भी अलग-अलग हैं। सभी आवासीय अपार्टमेंट, गुप हाउसगि सोसायटी, उद्योगों, खनन, और बुनयिादी ढाँचा परयोजनाओं को भूजल निकासी की मात्रा और मूल्यांकन इकाई की श्रेणी के आधार पर संकषेण शुल्क का भुगतान करना होगा।

**चुरमाना:** दशा-नरिदेशों में बनिा NOC के भूजल निकासी पर उद्योगों, खनन और बुनयिादी ढाँचे के प्रयोक्ताओं के लिये नयूनतम एक लाख रुपए का मुआवज़ा नरिदषिट किया गया है। इसके बाद जल निकासी की मात्रा और उल्लंघन की अवध के आधार पर इसे और बढ़ाया जा सकता है।

## सडक परविहन

### • केंद्रीय मोटर वाहन नयिमों में संशोधन

सडक परविहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन (11वां संशोधन) नयिम [Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules], 2020 को अधसूचिति कथिा। केंद्रीय मोटर वाहन नयिम (Central Motor Vehicle Rules), 1989 मोटर वाहनों के लिये लाइसेंस और परमटि तथा मानदंडों को वनियमिति करता है। मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **ई-चालान:** अधकृत अधकिारी अधनियिम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कसिी भी व्यक्त को इलेक्ट्रॉनकि तरीके से (या ऑटो जनरेशन के माध्यम से) चालान जारी कर सकता है।
- **इलेक्ट्रॉनकि प्रमाणपत्र:** 1989 के नयिमों में कहा गया था कि नरिरीक्षण के दौरान आवश्यक प्रमाण-पत्रों की वैध भौतिक प्रतलिपि को मंजूर कथिा जाएगा। संशोधति नयिम ड्राइवरों और कंडक्टरों को नरिरीक्षण और नयिमक अनुपालन की स्थिति में वैध इलेक्ट्रॉनकि प्रमाण-पत्र तथा फॉर्म रखने की अनुमति देता है। इसके अतरिकित दस्तावेज़ों को ज़ब्त करने की स्थिति में प्रमाण-पत्र एक नरिदषिट पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनकि तरीके से सौंपे जा सकते हैं।

### • फास्टैग

सडक परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधसूचना जारी की है जसिमें प्रस्ताव रखा गया है कि वर्ष 2017 से पहले बेचे गए सभी वाहनों में फास्टैग (FASTag) को अनवार्य कथिा जाए। इसके अतरिकित यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नयिम, 1989 में संशोधनों के माध्यम से थर्ड-पार्टी इश्योरेंस लेना अनवार्य कथिा जाना चाहिये।

फास्टैग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधकिरण द्वारा संचालति एक इलेक्ट्रॉनकि टोल संग्रह प्रणाली है। इसे वर्ष 2017 में नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण हेतु अनवार्य कथिा गया था।